विश्वविद्यालयों में शिक्षा का माध्यम

+

६६. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री प्रकाश वीर शास्त्री :

क्या **शिक्षा** मंत्री २६ नवम्बर, १९५९ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों के शिक्षण में भारतीय भाषाओं को कहां तक माध्यम बनाया जा सकता है इस प्रश्न पर विचार करने के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने कुछ समय पहले जो कार्यकारी दल नियुक्त किया था, उसने अब तक अपने कार्य में क्या प्रगति की है; और

(ख) उस दल का कार्य कब तक समाप्त हो जाने की आशा है ?

शिक्षा मंत्री (डा० का० ला० श्रीमाली) : (क) कायकारी दल का पहला अधिवेशन १५ फरवरी, १९६० को होगा।

(ख) अभी से बताना कठिन है।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, जबकि यह विषय इतना महत्वपूर्ण है तो क्या कारण है कि अभी तक कार्यकारी दल की एक बैठक भी नहीं हो पाई है ? और मैं जानना चाहता हूं कि इस कार्य में इतनी देरी क्यों की जा रही है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : आप जानते ही हैं कि इस काम को यूनिवर्स्टी ग्रांटस कमिशन कर रहा है और यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन के सामने जो समस्या है उसको वह अच्छी तरह से जानता है और उसको सुलझाने का प्रयत्न भी कर रहा है। आप जानते ही हैं कि यह काम बहुत कठिन है, आसानी से नहीं हो सकता है। जो कुछ काम यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ने किया है और जो कदम उठाये हैं, मेरे ख्याल से वे संतोषजनक हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन् क्या यह सत्य है कि आज से कई वर्ष पहले डा० राधाकृष्णन जी की अध्यक्षता में एक यूनिवर्सिटी कमीशन बिठाया गया था, और उसने भी यह सिफारिश की थी कि भारतीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा दी जाए और उसके बाद ऑफिशयल लैंगुएज कमीशन में भी इसका समर्थन किया था ? यदि यह सत्य है, तो ऐसे महत्वपूर्ण विषय में इतनी देरी किये जाने को क्या गवर्नमेंट उचित समझती है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : यह सच है कि राधाकृष्णन कमिशन ने यह सिफारिश की थी कि हमारी यूनिवर्सटी में शिक्षा का जो माध्यम है वह प्रादेशिक भाषायें या हिन्दी हो। लेकिन जैसा सदस्य महोदय जानते हैं कि यह सिफारिश यूनिवर्सिटी के लिऐ थी और जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटी हैं वे स्वतंत्र हैं इस मामले में और उन को कोई आदेश हमारी तरफ से नहीं दिया जा सकता है। हां इस बारे में सैंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की तरफ से सिफारिश जरूर की गई थी। जहां तक हमारा सम्बन्ध है हमने उस सिफारिश को मंजूर कर लिया था और इस सैंट्रल एडवाइजरी बोर्ड की रिकमेंडेशन को यूनिवर्स्टीस को भेज दिया गया था। अब यूनिवर्स्टी ग्रंटस कमिशन ने इस काम को उठाया है और मैं समझता हूं कि इसमें आगे प्रगति ठीक तरह से होगी।

Shri D. C. Sharma: May I know who the members of this Working Group are and whether they are members of other working groups of the Ministry of Education also?

Dr. K. L. Shrimali: I think the names of the members were given in that statement. Anyhow I will read them. They are—

Hindi—Prof. Virendra Verma, Prof. of Hindi, Allahabad University.

Punjabi—Sardar Niranjan Singh, ex-Principal of Khalsa College, Amritsar and Delhi (Chemistry).

Bengali—Prof. Buddha Dev Bose, Prof. of Comparative Literature (Bengali), Jadavpur University.

Marathi—Prof. G. D. Parekh, Rector of Bombay University.

Kannada—Prof. C. K. Venkataramiah, ex-Government Translator, Mysore Government.

Telugu—Dr. Govindarajulu, Vice-Chancellor, Sri Venkateswara University.

Tamil—Prof. Narayanaswamy Pillai of Annamalai University.

Malayalam—Prof. K. M. George, Assistant Secretary, Sahitya Academy, New Delhi.

Gujarati—Shri Maganbhai P. Desai, Vice-Chancellor, Gujarat University.

Oriya—Shri Sadasiva Misra, Principal, Ravenshaw College, Cuttack.

Assamese—Dr. Virinchi Kumar Barua of Gauhati University.

Urdu—Prof. A. A. Suroor of Aligarh Muslim University.

Kashmiri—Prof. J. N. Bhan, Prof. of Economics, Jammu & Kashmir University.

श्री बजराज सिंह : क्या यह सत्य है कि यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन उन यूनिवर्स्टीस के रास्ते में जो खुद हिन्दुस्तानी भाषाओं में पाठ्यक्रम रखना चाहती हैं रोक लगा रहा है और उन विश्वविद्यालयों को जोकि हिन्दुस्तानी भाषाओं में पाठ्यक्रम चलाना चाहते हैं, ग्रांट्स कम देता है या बिल्कुल नहीं देना चाहता है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इस प्रश्न को सुन कर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ है। यूनिवर्स्टी ग्रान्ट्स कमिशन स्वयं इस बात की कोशिश कर रहा है कि प्रादेशिक भाषायें माध्यम हो जाएं और उसके लिए वर्किंग ग्रुप बनाया गया है और सदस्य महोदय कहते हैं कि यूनिवर्स्टी ग्रांट्स कमिशन रोड़े अटका रहा है, यह तो उनका बड़ा आश्चर्यजनक प्रश्न है।

श्री रघुनाथ सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि संसार के स्वाधीन राष्ट्रों में केवल हिन्दुस्तान ही ऐसा देश है क्या, जहां पर कि अब भी मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन फारेन लैंगुएज है ?

डा० का० ला० श्रीमाली : इसके बारे में इस वक्त मैं कुछ नहीं कह सकता हूं लेकिन यह सही है कि हिन्दुस्तान में अभी माध्यम अंग्रेजी है और इस बात का प्रयत्न किया जा रहा है कि धीरे धीरे प्रादेशिक भाषायें माध्यम बन जाएं।

श्री बि० दास गुप्त : क्या मैं जान सकता हूं कि इस वर्किंग ग्रुप की टर्म्स आफ रेफ्रेंस क्या हैं और क्या यह वर्किंग ग्रुप यह भी तय करेगा कि किन किन यूनिवर्स्टीज में कौन कौन सी लैंगुएजज मीडियम आफ इंस्ट्रक्शन होंगी या मीडियम आफ एग्जेमिनेशन होंगी ?

डा० का० ला० श्रीमाली : जहां तक माध्यम का सम्बन्ध है, यह तो यूनिवर्स्टीज को ही तय करना पड़ेगा, उन्हीं को इसके बारे में फैसला करना होगा क्योंकि जैसा आप जानते हैं कि यूनिवर्स्टीज बड़ी हद तक स्वतंत्र है, आटोनोमस हैं। इस वर्किंग ग्रुप का काम यह होगा कि किस तरह से साहित्य का निर्माण किया जा सकता है कि पुस्तकों का अनुवाद किया जाय और इनके बारे में यह वर्किंग ग्रुप बैठ कर विचार करेगा।

Shri Sadhan Gupta: May I know if the terms of reference of the Working Group enables them to make recommendations for introducing the regional languages in administration as well as for purposes of commerce and industry side by side with making them the media of instruction so that employment to future University graduates may not be restricted by their education through the media of instruction?

Dr. K. L. Shrimali: This Working Group has a very limited purpose. It has been set up to study the question of adopting the Indian languages as the media of instruction in the Universities. It will not go into the questions which have raised by my hon. friend there.

Swami Ramanand Tirtha: Is there any proposal to make the regional languages the media of instruction for humanities and in the light of the experience gained in that respect to apply them to science and other subjects?

Dr. K. L. Shrimali: That is so. Gradually, we do want to change over to the regional languages.

Shri Ajit Singh Sarhadi: Pending suggestion by the Working Group, have any instructions been issued to the Universities themselves to switch on to the regional languages in the matter of the medium of instruction?

Dr. K. L. Shrimali: I have already explained that no directives or instructions can be issued to the Universities in this matter. The Universities are autonomous bodies and the University Grants Commission can only persuade them and request them. No instructions or directives can be given by the University Grants Commission in this matter. (*Interruption*).

Mr. Speaker: This has become a regular debate on the official language. I have been following every question that has been put and every answer that has been given. The hon. Members must have by this time learnt from the answers given by the hon. Minister that the adoption of any particular medium is in the hands of the universities themselves which are autonomous and all that the working group, as the agent of the University Grants Commission, can do is after they resolve upon having their own language as the medium of instruction, to see how best to accelerate the pace and to get along. Nothing more can be done. What is the meaning of going into all this? So far as the official language is concerned it is in the hands of the local legislature and the State Government and they could have the regional language as the official language in substitution of English. All that can be done.

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन माननीय मंत्री जी ने स्वीकार किया है कि कई वर्षों पहले इस सिद्धान्त को स्वीकार किया गया था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या विश्वविद्यालयों ने कोई कारण बतलाये हैं कि क्या अड़चनें हैं, या क्या कठिनाइयां हैं जिन की वजह से वे इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस में यह क्या कर सकते हैं?

डा० का० ला० श्रीमाली : जो कारण है वह हम सब लोग जानते हैं। कारण यह है कि अभी तक मौलिक पुस्तकें प्रादेशिक भाषाओं में नहीं हैं। न तो अनुवाद हैं और न मौलिक पुस्तकें लिखी गई हैं। जब तक मौलिक पुस्तकें तैयार न हों, मैं नहीं समझता कि युनिवर्स्टीयों के लिये यह सम्भव है कि वह प्रादेशिक भाषाओं में एक दम से बदल सकें।

Mr. Speaker: Shri Goray. He is a writer by himself.

Shri Goray: How many universities have adopted the regional language as the medium of instruction?

Dr. K. L. Shrimali: There are several which have adopted, but I do not have a statement here. If the hon. Member is interested, I will be glad to place a statement on the Table of the House.

Some Hon. Members *rose*—

Mr. Speaker: I am sorry, I shall have to proceed to the next question.

Coking Coal for Steel Plants

\+

*67. **Shri R. C. Majhi:**
Shri S. C. Samanta:
Shri Subodh Hansda:
Shri Mahanty:

Will the Minister of **Steel, Mines and Fuel** be pleased to state:

(a) how much coking coal is at present produced and supplied to the Steel Plants at Bhilai and Rourkela from the Coal Washery at Kargali;

(b) whether that quantity is sufficient;

(c) if not, how the deficit is met;

(d) whether it is also a fact that Jamshedpur and Burnpur Steel Plants are experiencing shortage of coking coal; and

(e) if so, whether orders have been placed for fresh coal-washeries?

The Parliamentary Secretary to the Minister of Steel, Mines and Fuel (Shri Gajendra Prasad Sinha): (a) During January 1960, the production of washed coal at Kargali Washery